against offenders and we have written to all State Governments and asked them to take drastic steps as they are doing in Punjab.

Shri Hem Barua: How can I carry this heavy burden?

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, खाद्य के अन्दर मिलावट के सिलसिले में पंजाबी सूबे और हरियाणा में जो व्यापारी पकड़े गए हैं उनका जो लगाव था वह भूतपूर्व मंत्रिमंडल के साथ था। तो क्या सरकार उन बड़े आदमियों पर भी हाथ डालने का विचार रखती है जो मंत्रिमंडल में थे और उसके अन्दर सम्मिलित थे ?

डा० सुशीला नायर : श्रीमन्, मुझे तो कुछ बात आपकी पूरी समझ में आई नहीं है .....

अध्यक्ष महोदय वह कहते हैं कि जो पकड़े गए हैं उनका कुछ सम्बन्ध पुराने मंत्रिमंडल से था। अगर बड़े आदमी होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी ?

डा० सुशीला नायर : बड़े छोटे का कोई लिहाज कानून नहीं करता। सब पर बराबर कानूनी कार्यवाही होगी ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय यह मंत्रिमंडल के अन्दर .....

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि कोई लिहाज नहीं करेंगे ।

अनुसूचित जातियों के लिये आर्थिक विकास कार्यक्रम

\+

*94. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अनुसूचित जातियों सम्बन्धी आर्थिक विकास कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिये उन्हें स्वयंसेवी संस्थाओं को सौंपने का प्रस्ताव है ;

(ख) सरकार अब तक किये गये कार्य से कहां तक सन्तुष्ट है; और

(ग) इस सम्बन्ध में पुनरीक्षित योजना को कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare (Shrimati Chandrasekhar): (a) At present there is no such proposal.

(b) Various measures and programmes have been undertaken and are being implemented by the State Governments. The progress is constantly reviewed and improvements are brought about whenever necessary. The Government is aware that still more has to be done in this respect.

(c) Does not arise.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, इन स्वयं-सेवी संस्थाओं में दो प्रकार के संगठन होते हैं, एक तो वे जो सरकार से किसी प्रकार की सहायता लिये बिना कार्य करते हैं, दूसरे वे संगठन होते हैं जो लगभग अर्ध-सरकारी या तीन चौथाई सरकार से होते हैं, जैसे भारत सेवक समाज, सोशल वेलफेयर बोर्ड आदि। इन स्वयं-सेवी संगठनों के सम्बन्ध में अब तक का सरकार का अनुभव क्या है ? जो पैसा सरकार ने अपनी इन अर्ध-सरकारी या तीन-चौथाई सरकारी संगठनों के द्वारा खर्च किया है, क्या उनके द्वारा अच्छा कार्य हुआ है या जो संगठन सरकारी सहयोग के बिना कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा अच्छा कार्य हुआ है ?

Shrimati Chandrasekhar: We assist all-India organisations which take up welfare programmes in the country, wherever voluntary organisations are capable of taking up this work on an

all-India basis, we assist them. If we find anything wrong with any organisation, we do not give the grant.

Mr. Speaker: He wanted to know what has been the experience of the Government, whether the organisations without the assistance and the patronage of the Government have done better in this field or the Government inspired agencies have done it better.

Shrimati Chandrasekhar: We have no report to that effect.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि चतुर्थ पंच वर्षीय योजना बनाते समय अनुसूचित जातियों के विकास के लिए जो कार्यक्रम सरकार तैयार कर रही है, उसमें पहले की अपेक्षा, चूंकि उनके लिये अधिक कार्य नहीं किया गया, इस लिये उस राशि को बढ़ायेगी या उस राशि को घटाने का विचार है ?

Shrimati Chandrasekhar: In the Fourth Plan, we do intend giving a little more assistance to voluntary organisations to carry out welfare programmes.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि ये जो सुरक्षित स्थान रखे गये हैं, एक-क्लास, दो-क्लास, तीन-क्लास, चार-क्लास तक क्या ये सब के सब भर दिये गये हैं, यदि नहीं तो कितने खाली हैं और उनके भरने के लिये सरकार कौन सा कठोर कदम उठा रही है तथा कब तक वे भर दिये जायेंगे तथा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि देश में छुआ-छूत कितने प्रतिशत कम हुई है ?

Shrimati Chandrasekhar: This question for it is given, I may be able to give of this Question. If a separate notice for it is given. I may be able to give an answer.

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि हरिजनों में भी दो-एक जातियां ऐसी हैं जो कि सारे का सारा फायदा उठा लेती हैं, लेकिन बहुत सी छोटी-छोटी जातियां ऐसी हैं, जिनको एक पैसा भी नहीं मिलता। क्या कोई ऐसा प्रबन्ध होगा कि जो छोटी-छोटी जातियां हैं और जिनको कोई सहायता नहीं मिलती है, उनको भी सहायता पहुंच सके ?

श्री हुकम चन्द कछवाय : चमारों को ज्यादा मिलती है और किसी को नहीं मिलती।

Shrimati Chandrasekhar: Even though this question also does not fall within the purview of this.....

Mr. Speaker: His question was that all castes are not given the same facility equally, that there are certain castes that are monopolising all the aid that is being given. This is what he means to say.

Shrimati Chandrasekhar: In our welfare programmes we do take care that the weakest of the weaker sections do get it.

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या सरकार को पता है कि अनुसूचित जाति के लोगों की आर्थिक अवस्था बहुत ही हीन है तथा उनके उत्थान के बहाने कुछ साम्प्रदायिक संस्थायें प्रलोभन देकर उनका बलात् मत परिवर्तन करती हैं। उदाहरण के लिये निकोबार में 15 हजार में से 13 हजार का मत परिवर्तन कर दिया गया, क्या सरकार उनकी गरीबी को दूर करके ऐसे मत-परिवर्तन को रोकेगी ?

Mr. Speaker: That is a different question.

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : उनकी आर्थिक अवस्था के कारण ऐसा होता है, उनका कनवर्शन हो रहा है, इसलिये यह प्रश्न किया है।

श्री बड़े : उनकी आर्थिक अवस्था बहुत खराब है, उनकी डवेलपमेंट के लिये पूछा है।

Mr. Speaker: The question is that on account of their helplessness, they fall victims for conversions by other religions; would the Government see that such conversions do not take place and that their condition is improved very soon or something like that.

Shrimati Chandrasekhar: In the main body of the answer I have said that we are taking more programmes for the economic development of the weaker sections. As regards our assistance to voluntary organisations, the list that I have with me does not say that any such organisation has been assisted to bring in such a large number of conversions.

श्री गणपति राम : क्या सरकार को ज्ञात है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के रिव्यू के बाद और शेडयूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद यह सत्य स्थापित कर दिया गया कि पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को योजनाओं का जितना फायदा मिलना चाहिये था, उतना नहीं मिल सका है । क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्स के आर्थिक , सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिये कोई स्पेशल प्रोग्राम रखा जाने वाला है, जिससे पिछली तीन योजनाओं का घाटा पूरा किया जा सके ?

Shrimati Chandrasekhar: It is not very correct to say that no benefit has been drawn by the scheduled castes in the First, Second and Third Plans. Nearly 89 to 90 per cent of the allotted funds are utilised; we can see from the experience.

As regards special programmes, we are thinking of special programmes for the economic development in the Fourth Plan.

Shri Jaipal Singh: May I know whether all these voluntary organisations which receive money from Government are recognised and duly registered. What machinery is there to see that the money that is given is spent in the proper way? Do they come within the purview of the Comptroller and Auditor General?

Shrimati Chandrasekhar: They may not come within the purview of the Comptroller and Auditor General. But the organisations which are assisted by us will have to have one member of Government on the Committee and they have to send audited accounts every six months. Unless they send the utilisation certificates, further grants are not released to them.

श्री शिव नारायन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे लड़के एम० ए० पास हैं, बी० ए० पास हैं , हमारे पास लखनऊ में एक एम० एस० सी० फर्स्ट क्लास पास लड़का है, लेकिन आज तक उसको सर्विस नहीं मिली । जो रिजर्वेशन आपने हम को दे रखा है, उस में कितना आपने फुलफिल किया है ? (**व्यवधान**)

हमारा लड़का नहीं है, अध्यक्ष महोदय, यू० पी० का लड़का है, एम० एस० सी० फर्स्ट क्लास है, वह स्टेट गवर्नमेंट में जा कर मिला, लेकिन कछ नहीं हुआ । बाबू रघुनाथ सिंह ने कहा कि चमार को जगह मिल गई है, इस लिये मैं ने कहा है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैंने कभी नहीं कहा है कि जगह मिल गई है ।

श्रीमती लहोदराबाई राय : जैसाकि हमारे माननीय साथी श्री रघुनाथ सिंह ने कहा है हमारे हरिजनों में 80 प्रतिशत हरिजन ऐसे हैं जो कि इस लाभ से वंचित रह जाते हैं । मैं ने सारे हिन्दुस्तान में चलकर और घूमकर देखा है कि इस का केवल मुट्ठी भर लोगों को ही फ़ायदा मिलता है बाकी के तमाम हरिजन इस से वंचित रह जाते हैं, देहातों की तरफ के हरिजनों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, उनकी कोई तरक्की नहीं

हुई है और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है और न उनका कोई नाम लेने वाला है

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये ।

श्रीमती सहोदराबाई राय : इसलिए मैं मंत्राणी महोदया से पूछना चाहती हूं कि क्या वे इसका फायदा सब हरिजनों को देंगी, या सिर्फ थोड़े से आदमियों को ही दे देंगी?

अध्यक्ष महोदय : प्रार्थना आप ने सुन ली जो कि वह सुनाना चाहती थीं अब जवाब दे दीजिये ।

Shrimati Chandrasekhar: Could I have it translated into English?

Mr. Speaker: The first part was only a suggestion and a request. In the second part, she wants to enquire about something, and I could not follow exactly what she had said. If the Deputy Minister has followed the question, she might answer.

Shrimati Chandrasekhar: We do take....

Mr. Speaker: Her question was the same as was asked by Shri Raghunath Singh earlier. There are some castes that are not getting their share of aid, and the hon. Member wants to know whether Government would see that it is equitably distributed among all the castes.

Supply of Filtered Water in Calcutta

*95. **Shri C. K. Bhattacharyya:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the growing problem of filtered water supply in Calcutta; and

(b) whether the State Government have requested the Central Government for any aid to be given to the Calcutta Corporation to set up 60 reservoirs in the worst affected wards each with a capacity of 450 gallons.

1015(ai)LS—2.

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri B. S. Murthy): (a) Yes, Sir.

(b) No such request has been received.

Shri C. K. Bhattacharyya: In his statement to some organisation, the chairman of the Standing Committee on Water Supply stated on the 24th May that these 60 reservoirs would be installed within the next ten days. Would the hon. Minister give us any information whether these 60 reservoirs or any of them have been installed?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): It is not possible for us to give information with regard to the 60 reservoirs, because we have no information about it. But I might say that the State Government had asked for financial assistance, and so far, Rs. 101.39 lakhs of loan has been given for water supply and gas supply schemes to the Calcutta Corporation. They wanted another sum of Rs. 15.12 lakhs, and I am glad to say that the Finance Ministry has agreed to provide that also.

Shri C. K. Bhattacharyya: Is it known to the hon. Minister that there is a great lack of sufficient supply of drinking water to Calcutta and the surrounding municipalities?

Dr. Sushila Nayar: Yes; these scheme include four water supply schemes for the municipalities of Dum Dum, North Dum Dum, Dum Dum South and Hooghly Chinsura.

Dr. Ranen Sen: The hon. Minister has just now said that money has already been sanctioned by the Finance Ministry to the Calcutta Corporation through the State Government for the supply of filtered water to the city of Calcutta. May I know whether there is any arrangement or machinery with the Government of India to find out how the